











## डिजिटल घोटाले

## प्रधानमंत्री की चेतावनी

A portrait of Prime Minister Narendra Modi. He is wearing a light green kurta and has a white beard. He is pointing his right index finger upwards while speaking. The background is blurred, showing the Indian national flag.

करेगो। अतः ऐसे किसी कृत्य को संदेह से देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों को फौरन राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन तथा स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत करनी चाहिए। देश में 'डिजिटल अरेस्ट' के अनेक मामले सामने आए हैं जिनसे घोटाले की व्यापकता पता चलती है। हाल ही में मलयालम फिल्म अभिनेत्री माला पार्वती भी इस घोखाधड़ी का शिकायत हुई। स्वयं को मुंबई के पुलिस अधिकारी बताते हुए घोटालेबाजों ने उन पर ताइवान से नशे की तस्कीने के आरोप लगाए। सौभाग्य से उन्होंने पैसा देने के पहले ही घोटालेबाजों को पहचान लिया। 'डिजिटल अरेस्ट' मामले कुल घोटालों का बहुत छोटा हिस्सा है। रोज लाखों लोग घोटालेबाजों के शिकायत बन कर अपना पैसा गंवा देते हैं। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे डिजिटल घोटाले लोगों में कानूनी व्यवस्था के प्रति भय का लाभ उठाते हैं। घोटालेबाज अक्सर स्वयं को पुलिस अधिकारियों, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई अधिकारियों या केन्द्रीय बैंक प्रतिनिधियों की तरह पेश करते हैं जिससे उनके द्वारा दी जाने वाली धमकियां विश्वसनीय लगें। 'डीपफेक तकनीक', फर्जी आईडी कार्ड व अच्छी तरह तैयार पृष्ठभूमि उनके दावों को आधिकारिकता प्रदान करती लगती है जिससे वे भय पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी सामयिक है, पर प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर सुरक्षा मजबूत कर घोटालेबाजों को पकड़ना चाहिए। सर्वोच्च स्तर पर साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल है। इस दिशा में जागरूकता अभियानों, साइबर अपराध हेल्पलाइनों तथा तकनीकी कंपनियों से बेहतर सहयोग कर घोटालेबाजों पर लगाम लगानी जरूरी है।

संतुलन और  
सामंजस्य के  
सिद्धांतों पर  
आधारित आयुर्वेद  
व्यक्तियों को  
समग्र स्वास्थ्य  
प्राप्त करने के लिए  
मार्गदर्शन करता  
है।

**प्रतापराव जाधव**  
(लेखक, स्वास्थ्य एवं  
परिवार कल्याण राज्य  
मंत्री हैं)

**विषय** शब्द आयुर्वेद दिवस, जो हार साल भगवान् धन्वंतरि जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, भारत के स्वास्थ्य और कल्याण की समृद्ध विरासत का सम्मान करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष, 29 अक्टूबर 2024 को, हम आयुर्वेद को न केवल एक प्राचीन उपचार पद्धति के रूप में बल्कि एक जीवन परम्परा के रूप में मान्यता देने वेलिए एक साथ आते हैं जो दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करती रहती है।

संतुलन और सामंजस्य के सिद्धांतों पर आधारित आयुर्वेद व्यक्तियों को उनके अद्वितीय मन-शरीर की संरचना के लिए भौमि वाई जाती है।

## समझकर आर प्रकृत का लय क सार

---

प्रदूषण की मार

हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा खराब पाया गया। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम व फरीदाबाद में भी कमोवेश यही स्थिति है। वातावरण में इतना ज्यादा प्रदूषण घुला हुआ है कि आमजन को सांस लेने में आ रही परेशानियों से श्वसन तंत्र दुष्प्रभावित हो रहा है। हवा में मौजूद प्रदूषण के मुख्य कारकों में वाहनों से उत्सर्जित धुआ, टूटी फूटी सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में जलते चूल्हे, औद्योगिक इकाइयों से निकलती जहरीली गैसें, पंजाब व हरियाणा के खेतों में कुछ गैर-जिम्मेदार किसानों द्वारा पराली जलाना, त्योहार मनाने की आड़ में आतिशबाजी एवं पटाखों का चल, आदि शामिल हैं। दीपोत्सव पर्व में पटाखों के प्रयोग को हतोत्साहित करना पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से समय की मांग है। हालांकि, सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रयास करती है, पर आम जनता को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण पर राज्यों व केन्द्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेदों को किनारे रख कर सहमति बननी चाहिए तथा इसका जर्मीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदूषण की मार से त्रस्त जनता को राहत दिलाना सभी राजनेताओं का कर्तव्य है।

यगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

कुण्डल परिषार रामा, नरादाम

## प्रदूषण की मार

## ज्लोबल वार्मिंग का खतरा

राष्ट्रसंघ महासचिव अंटोनिओ गुटेरेस ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि पृथकी गर्म और अधिक खतरनाक होती जा रही है जहाँ गर्मी की लहरें 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुँच रही हैं। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी लोगों की जान ले रही है, अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रही है और असमानताओं को बढ़ा रही है। इस पद को संभालने के बाद से ही वे जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्पर्जन के बढ़ते खतरे के बारे में दुनिया को सचेत करते आ रहे हैं। मगर दुनिया के कर्तव्याधीन सिफर हर साल संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन- कॉम्मेंस ऑफ वार्टाज़ में भाग ले कर संतुष्ट हो जाते हैं। इस साल इसका 29वां सम्मेलन अज़्रबैजान में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इसमें अच्छे-अच्छे भाषणों के सिवा कोई और उम्मीद नहीं है। बिगड़ते मौसम की मार आम आदमी ज़ेलता आ रहा है और आगे भी ज़ेलता रहेगा। बाढ़, सूखा, जंगलों में आग, तूफन, समुद्री तूफान तथा समुद्र के स्तर में बद्धि का खामियाजा आम लागों और समाज के सबसे गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग व उससे पैदा प्रदूषण संकट के कारण दुनिया के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर विस्थापन भयावह रूप ले रहा है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

## आप की बात

---

— 1 —

आयुर्वद का महत्व  
भारतीय ऋषियों द्वारा सदियों से दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जा रहा है। एलोपैथिक दवाइयों के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई भले ही कुछ धीमा असर करती हों, मगर यह कई असाध्य रोगों को जड़मूल से ख़त्म कर सकती है। उचित मात्रा में उपयोग करने पर आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जबकि एलोपैथी दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक और स्ट्रेरॉयड भयानक साइड इफेक्ट पैदा कर सकती हैं। इनका उपयोग एक बार करने के बाद इनकी आदत पड़ जाती है, जिसके चलते दवा का डोज़ और उसके साइड इफेक्ट भी बढ़ते जाते हैं।

आयुर्वेदिक इलाज में किसी प्रकार की महंगी जांच आदि पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और सस्ते में इलाज हो जाता है। अब लोगों का विश्वास भी आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति बढ़ने लगा है। कोरोना काल में आयुष काढ़े का उपयोग करने वालों को बहुत लाभ मिला। इससे अनेक लोगों को मामूली समस्याओं से राहत मिली और अस्पताल नहीं जाना पड़ा। सरकार भी अब आयुर्वेदिक इलाज को बढ़ावा दे रही है। पातंजलि समेत अनेक संस्थाएं इन पर शोध कर रही हैं जिससे भविष्य में परिष्कृत हो कर आयुर्वेदिक इलाज और अधिक असर कारक होगा।

-विभिन्न वपक्या, खाचरोद

**मुफ्तखारा का आदत**

मुफ्तखोरी की आदत नागरिकों को पंगु बनती है, मगर वोटों की राजनीति के चलते अब देश भर में सभी राज्य सत्ता में आने के लिए इस अप्रत्यक्ष रिश्त का उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते लगभग सभी राज्य कर्ज में आकंठ डूबे हुए हैं। मगर सत्ता के लिए राजनेता यह सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हैं। मुफ्त की सभी योजनाओं पर सरकार जितने रुपए खर्च कर रही है यदि यही पैसा लोगों को खुद के रोजगार के लिए आवंटित किया जाए तो जनता पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकती है। दूसरे कर्ज मापे के चलते बैंकों की हालत पतली हो रही है, मगर सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर ही रेवड़ी कल्चर को सख्ती के साथ बंद करना होगा। यदि राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ीयां बांटना ही चाहते हैं तो अपने पार्टी फंड से बाटे। यदि यही स्थिति रही तो राज्यों को कर्ज मिलने पर रोक लगानी पड़ेगी। मुफ्त की रेवड़ीयां बांटने से विकास और निर्माण कार्य के लिए सरकार के पास पैसा नहीं बचता।

**सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम**

[responsemail.hindipioneer@gmail.com](mailto:responsemail.hindipioneer@gmail.com)











